डी-ब्लॉक अशोक नगर (साहिबाबाद)
प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन (आर. ई. जी. डी.)
वी.
राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य।
अप्रैल 29, 1997
[के. रामास्वामी, एस. सागर अहमद और जी. बी. पटनायक, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894ः

1984 के संशोधन अधिनियम के तहत ऋण और ब्याज - पुरस्कार की पात्रता- अंतिम हो जाने के बाद, आवास एवं विकास परिषद का यह रूख कि वे संशोधित अधिनियम के तहत धन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नही है, इस प्रकार नहीं हो सकता है। दावेदार शेष राशि के हकदार हैं उन दावेदारों के लिए जिनकी भूमि पर ब्याज लिया गया है, उनकी गणना अधिनिर्णय के अनुसार कब्जा करने की तारीख से जमा करने की तारीख तक की जाएगी।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3571/1997.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 6.5.96 दिनंाकित निर्णय और आदेश सं. C.M.W.P सं. 13550/921

आर. के. गुप्ता और सुधीर कुमार गुप्ता अपीलार्थी के लिए गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए पी. के. जैन और ए. के. गोयल।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

छुट्टी दे दी गई।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अल-लाहाबाद उच्च न्यायालय के फेसले से उत्पन्न होती है, जो सीएमडब्ल्यूपी संख्या 13550/92 में 6.5.1996 पर किया गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना संक्षेप में, भूमि के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण करने वाला 'अधिनियम' 26 जून 1982 को प्रकाशित किया गया था। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 27 फरवरी, 1989 को धारा 11 के तहत 5 लाख रूपये का मुआवजा देते हुए अपना पुरस्कार 50 रू. दिया

था। अंतिम हो जाता है, आवास एवं विकास परिषद द्वारा लिया गया रूख कि वे संशोधित अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और दावेदार अनुसूची के तहत 15 प्रतिशत पर मुआवजे ओर 6 प्रतिशत पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं यू. पी. आवास एवं विकास अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह हैः देय शेष राशि क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें, उन्होंने कहा है कि 1157.895 एकड़ में फेली भूमि के लिए, रूपये की राशि में मुआवजा। 52,05,94, 187.90 तय किया गया था। जिसमें से रू. 42,15,00,000 जमा किया गया था और शेष राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी जैसा कि श्री राजीव कुमार सिंह के 10 दिसंबर, 1992 के पत्र में स्वीकार किया गया था। रूपये की शेष राशि। 3,26,22, 583.25 इसलिए, उन्हें देय है। ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब भूमि अधिग्रहण अधिकारी अधिनिर्णय होने के बाद भूमि पर कब्जा कर लेता है। परिषद की ओर से कहा गया है कि केवल 9.2 की सीमा का कब्जा। अकेले एकड़ भूमि वितरित की गई और बाकी भूमि वितरित नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व केवल कब्जा लेने की तारीख से ही उत्पन्न होता है और जैसा कि यह दावा किया जाता है कि भूमि की पूरी सीमा पर कब्जा नहीं दिया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है कि पुरस्कार के बाद किस क्षेत्र का कब्जा दिया गया है, उन दावेदारों के लिए जिनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, ब्याज की गणना अधिनिर्णय के अनुसार कब्जा लेने की तारीख से जमा करने की तारीख तक की जाएगी और तदनुसार ब्याज निर्णय की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नही।

अपील की अनुमति दी गईं।